

काशी-तमिल संगमम सांस्कृतिक एकता का सूत्र



सी.पी. साहाकुबान
उपराष्ट्रपति, भारत

भारत की सनातन सांस्कृतिक आत्मा को यदि किसी एक पवित्र मंच पर सजीव रूप में देखा जा सकता है, तो वह है काशी-तमिल संगमम. यह एक ऐसा अनूठा उत्सव है, जहां उत्तर और दक्षिण की संस्कृति, सभ्यताएँ, भाषाएँ और परंपराएँ, एक विराट भारतीय परिवार की तरह एक-दूसरे का आलिगन करती हैं. संगमम के चौथे संस्करण के अवसर पर मैंने और भी गहराई से यह अनुभव किया कि काशी और तमिलनाडु का यह संबंध केवल भौगोलिक या ऐतिहासिक नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से बहती आध्यात्मिक सांस्कृतिक धारा का अखिल प्रवाह है. काशी अविनाशी है, अनादि काल से है.

काशी को प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की राजधानी कहा जाता है. दूसरी ओर, तमिलनाडु, जिसकी भाषा विश्व की प्राचीनतम जीवित भाषाओं में से एक है, भारत की सनातन परंपरा, साहित्य, संगीत और दर्शन का महान वाहक रहा है. काशी-तमिल संगमम इन दोनों सभ्यतागत स्तंभों के बीच के सेतु को पुनः सुदृढ़ करता है.

उत्तर और दक्षिण के बीच यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान कोई नया प्रसंग नहीं है. देवारम नालवर के भक्ति गीतों से लेकर काशी में गुंजते संत कबीर के निर्गुण भजनों तक साधना की भाषा एक ही रही है और वह भाषा है भक्ति, ज्ञान और मानवता की भाषा. काशी में तमिल संतों की उपस्थिति, और दक्षिण भारत में काशी को 'मोक्ष की नगरी' के रूप में

मान्यता, इस गहरे संबंध को प्रमाणित करती है. हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और एक भारत, श्रेष्ठ भारत के दृढ़ संकल्प से 2022 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ.

आज यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है. यहाँ गंगा की संस्कृति और कावेरी की परंपराएँ एक-दूसरे से मिलकर भारत की सांस्कृतिक अखंडता को आगे बढ़ाती हैं. प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 'मन की बात' में इस उत्सव का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह संगमम विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक काशी और विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक तमिल का संगम है. उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृति को भारत का गौरव बताते हुए सभी से तमिल सीखने का आग्रह भी किया. यह आग्रह केवल भाषाई आग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक सशक्त संदेश है. इस वर्ष संगमम का ध्येय भी आओ तमिल सीखें है. भारत की भाषाई विविधता को अपनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

काशी-तमिल संगमम 4.0 नए आयाम, नई सहभागिता- काशी-तमिल संगमम के प्रत्येक संस्करण में तमिलनाडु के छात्र, अध्यापक, लेखक और मीडिया प्रोफेशनल्स, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लोग, महिलाएँ, और आध्यात्मिक विद्वान सात से दस दिनों के लिए काशी आते रहे हैं.

इस दौरान वे काशी के मंदिरों, तमिल से सम्बंधित केंद्रों और अयोध्या और प्रयागराज जैसे नगरों से परिचित होते हैं. चौथे संस्करण ने संगमम की सीमा और महत्वाकांक्षा दोनों को बढ़ाया है.

काशी-तमिल संगमम 4.0 में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है.



विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का उद्देश्य भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता की चेतना को और गहराई देना है. संगमम के दौरान, उत्तर प्रदेश के 300 विद्यार्थी तमिलनाडु पहुंचे हैं और विभिन्न संस्थानों में तमिल भाषा सीख रहे हैं. उन्होंने तमिलनाडु की समृद्ध परंपराओं, त्योहारों और भारतीय परंपरा की एकता से भी परिचित कराया जाएगा. तमिलनाडु से भी पचास तमिल शिक्षक वाराणसी पहुंचे हैं और संगमम के दौरान 1,500 से अधिक छात्रों को तमिल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं. तमिल की मधुर ध्वनि काशी में गुंजी, इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है? काशी-तमिल संगमम 4.0 की एक और विशेषता और प्रेरक पहल 'अगस्त्य अभियान' है. यह अभियान तमिलनाडु के तेनकाशी से काशी तक एक प्राचीन सभ्यतागत मार्ग को

पुनर्स्थापित करता है. महर्षि अगस्त्य भारतीय सभ्यता के उन महान ऋषियों में से हैं, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक संवाद को सुदृढ़ किया. उन्हें तमिल भाषा और सिद्ध चिकित्सा का प्रवर्तक माना जाता है. वो तमिल संस्कृति को उत्तर भारत तक ले कर आये.

अगस्त्य अभियान उनके उसी योगदान को स्मरण करते हुए उत्तर-दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों को पुनः रेखांकित करता है. यह यात्रा पांडियन शासक आदि वीर पराक्रम पांडियन की विरासत का भी सम्मान करती है. उन्होंने सांस्कृतिक एकता का संदेश फैलाने के लिए उत्तर भारत की यात्रा की और दक्षिण में एक शिव मंदिर बनवाया, जिससे उस जगह का नाम तेनकाशी (दक्षिण काशी) पड़ा.

एक भारत, श्रेष्ठ भारत- संगमम की आत्मा- काशी तमिल संगमम 4.0 ने यह स्पष्ट

किया है कि भारत सरकार सांस्कृतिक एकीकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. इस आयोजन ने विभिन्न समुदायों को जोड़ा है. इसने यह पुनः स्थापित किया है कि भारत की सभ्यतागत शक्ति उसकी विविधता की एकता में निहित है.

आज जब विश्व विविधताओं के बीच तनाव और संघर्षों से जूझ रहा है, तब भारत का विविधता को उत्सव के रूप में स्वीकार किया जाना, वैश्विक संदर्भ में भी प्रेरणास्पद बनकर उभरता है. महाकवि सुब्रमण्य भारती ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ सिंधु तट पर तेलुगु गीत गाए जाएँ और कावेरी की धरती के बच्चे गंगा के तट पर उत्सव मनाएँ, उस स्वप्न ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से आज मूर्त रूप ले लिया है. इस संगमम से प्रेरणा लेकर हम कह सकते हैं-

कावेरी की पुत्री, गंगा के तट पर गाती है, भक्ति की मधुर धारा में, अपनी धुन मिलाती है. गंगा का पुत्र भी, कावेरी के तट पर आता है, तमिल के मीठे स्वरों में, भारत का नाद सुनाता है.

काशी से शुरू हुआ यह कार्यक्रम, तमिल आध्यात्मिक विरासत की सबसे पवित्र जगहों में से एक रामेश्वरम में खत्म होगा. यही वह सेतु है जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है, और भारत को एक परिवार होने की अनुभूति कराता है.

मुझे विश्वास है कि यह संगमम सदैव जगमगाता रहेगा तथा काशी और तमिलनाडु का यह संबंध और भी गहरा होता जाएगा. जय हिंद! जय भारत!

सभ्यतागत संवाद से भविष्य की ओर काशी-तमिल संगमम 4.0 यह संकेत देता है कि भारत अपनी प्राचीन सभ्यतागत जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है. यह आयोजन हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अतीत की स्मृतियाँ केवल विरासत नहीं, बल्कि वर्तमान को दिशा देने वाली प्रेरणा होती हैं. ऐसे मंचों के माध्यम से सांस्कृतिक संवाद, आंतरिक एकता और राष्ट्रीय चेतना को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. काशी-तमिल संगमम अतीत की सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान की जीवंत सहभागिता और भविष्य के विकसित भारत 2047 जैसे राष्ट्रीय संकल्प, तीनों को एक सूत्र में पिरोता है. यह स्पष्ट करता है कि भारत का विकास केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सभ्यतागत चेतना में निहित हैं.



जो है उसे संरक्षित कर लें



संदीप खेमराजा

रिश्ते बिखर रहे हैं. बरसों के करीबी रिश्ते भी! पति पत्नी के ही नहीं, भाई भाई के, भाई-बहनों के, माता पिता से बच्चों के! सगी बहनों के भी. दूर के रिश्ते तो पहले ही औपचारिकता तक सीमित हो गए. रिश्ते की मजबूत नींव प्रेम, त्याग और सम्मान पर टिकी होती है. कहीं न कहीं यह नींव हिलती है, तभी करीबी रिश्तों की इमारतें भी धराशायी हो जाती हैं.

सात जन्मों की कसमें खाने वाले दंपति, दो चार साल में ही एक दूसरे से उठने लगे हैं. संपत्तियों के लिए सगे भाई बहनों में कोर्ट कचहरी हो जाती है. बीस पच्चीस वर्ष की उम्र के बच्चे, माता पिता से दूरी बना लेते हैं! किसी को कुछ कहा नहीं कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है. करीबी रिश्तों की करवट लेती ये स्थितियाँ घरों में घोर कूट और संवादहीनता का वातावरण निर्मित कर रही है. पारिवारिक पृष्ठभूमि की समृद्धता वाला यह देश पश्चिमी दुनिया की राह तेजी से पकड़ रहा है. दरकते रिश्तों की किसी को कोई ग्लानि भी नहीं है. अपने हाल में सब सहज महसूस करने लगे हैं.

ऐसा क्या बदल गया बीते कुछ वर्षों में, जिससे रिश्तों की डोर इतनी कमजोर पड़ गई.

- स्वतंत्रता की बड़ी ख्वाइश!
- अपेक्षाओं की बेतहाशा वृद्धि!
- स्वार्थ का हावीपन!
- समर्पण का सर्वथा अभाव!
- सम्मान देने लेने में कंजूसी!
- समायाभाव का झूठा हवा!
- अहंकार का टकराव!!

ये तो प्रमुख कारण हैं ही. इसके अलावा, सोशल मीडिया की सेंध. व्यक्ति का इतना समय यह खा जाता है कि अपनों से बात करने का समय ही नहीं बचता! बच्चे, जवान, अंधेड़ सभी लगे पड़े हैं. रीलों देख देख कर अनजाने ही स्वयं का नया वर्जन तैयार हो रहा है. अधिकांश रीलों समूची मानसिकता को ही बंधक बना रही है.

पूरा व्यक्तित्व एक ही एल्गोरिथम में फंस कर करपट हो रहा है. नजर नहीं आ रहा लेकिन परिवारों का सर्वनाश करने में महत्वपूर्ण कड़ी का काम ऑटो मोड में हो रहा है. यों समय का सबको अभाव है, लेकिन प्रतिदिन चार पांच घंटे मोबाइल पर लगे रहना आम बात है. दूसरा, जो प्राप्त है उसके प्रति कृतज्ञता का सर्वथा अभाव. भौतिक दृष्टि से जो नहीं मिल रहा (या अत्यंत कपास है और भेरे पास नहीं) उसकी तृष्णा, तड़प और कूटा अवश्य है.

चिंतन में पूरी तरह बस अन्त्यों से तुलना है. मजे की बात यह कि यह तुलना अपने से कमजोर से नहीं, अपने से अधिक समृद्ध से ही है! और, यही अपेक्षा का दबाव, कब दरारें पैदा कर देता है, रहस्य रह जाता है! तुलना ही करनी है तो केवल भौतिकता या समृद्धि की ही क्यों होनी चाहिए? यदि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, प्रेम और सामंजस्य से भरापूरा परिवार है, सम्मान और आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो यह सब क्या कम है? सद्भावना, संतुष्टि और शांति से जीवित चल रहा है तो निश्चित ही उन सब अधिक समृद्धशाली लोगों से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, जहां इनका अभाव है! और, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि अत्यधिक समृद्धि दें या न दें, लेकिन इन चीजों को बनाए रखें! यकीन मानना, आप अधिक गौरवशाली होंगे. और, उसमें भी मुख्य बात, गौरव की अनुभूति कराने वाली इन चीजों की अहमियत समझिए और इनका किसी भी कीमत पर संरक्षण कीजिए!



दिनेश गुप्ता

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन की नई टीम नए साल में ही आएगी. लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि सूची जनवरी में ही आ जाए. फरवरी-मार्च या जून भी हो सकता है. साल 2026 में तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं. पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु. बिहार के बाद अब भाजपा तीनों ही राज्यों में द्रुम धमाकेदार प्रदर्शन करना चाहती है. सबसे दिलचस्प मुकाबला पश्चिम बंगाल में होना है. 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे दमदार प्रदर्शन किया था. पिछले चुनाव परिणामों के बाद ही यह कहा जाने लगा था कि भाजपा इससे ज्यादा ताकत अब आगे नहीं लागा पाएगी. भाजपा इन अटकलों को झुटलाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है.

पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर के दर्शन के साथ दिखाई देते थे. इस बार वंदे मातरम के जरिए बंगालियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. कोशिश पश्चिम बंगाल में रह रहे बिहारी और झारखंड के नैऋत्य दिशाओं को साधने की भी है. नितिन नबीन की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी क्या बिहारियों को साधने की कवायद का हिस्सा है? पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच संबंध ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक हैं, जिसमें बिहार पहले बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था और बाद

में अलग हुआ. आज भी दोनों राज्यों के लोग नौकरियों और अन्य अवसरों की तलाश के लिए एक-दूसरे के यहाँ आते-जाते रहते हैं.

खासकर बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में श्रमिक और व्यवसायी के रूप में बड़ी संख्या में मौजूद हैं. ये वहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को प्रभावित करते हैं. राजनीति में भी दोनों राज्यों के मुद्दों का



प्रभाव दिखाता है. यही कारण है कि बिहार में भाजपा की जीत को बंगाल जीत का आगाज माना जा रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से भले दूर रह गई हो, लेकिन 77 सीटों तक पहुंचना असाधारण खलंग के तौर पर देखा गया. खासकर उत्तर बंगाल, जंगल महल और आदिवासी बहुल इलाकों में भाजपा की पैठ ने तुणमूल कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी की है. ममता बनर्जी इस बार उसी

सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करने में जुटी हैं, जहां कहीं न कहीं भाजपा सेंध लगाने में सफल रही थी. पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में झारखंड का भी प्रभाव दिखता है. यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगली राजनीतिक भूमिका पर अटकलें चल रही हैं. पश्चिम बंगाल के झारखंड से सटे जिलों में आदिवासी मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है. यही वह क्षेत्र है, जहां झामुमो की ऐतिहासिक स्वीकार्यता रही है. दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इन इलाकों में लंबा राजनीतिक

जुड़ाव रहा है. वे न केवल झारखंड, बल्कि बंगाल के आदिवासी इलाकों में भी सम्मान और पहचान रखते थे. यही विरासत आज हेमंत सोरेन के राजनीतिक कद को इन क्षेत्रों में प्रभावशाली बनाती है. बंगाल में लगभग एक दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां झामुमो की भूमिका गेम चेंजर हो सकती है. झामुमो यदि सीधे चुनाव लड़े या तुणमूल के साथ स्पष्ट तालमेल में जाए तो आदिवासी वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने में ममता बनर्जी को लाभ मिल सकता है. खासकर वहां, जहां भाजपा ने आदिवासी असंतोष को मुद्दा बनाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है. हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी के राजनीतिक रिश्ते नए नहीं हैं. गैर भाजपा शासित

प्रांतों, संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के सवाल पर दोनों नेताओं की सोच में साम्य दिखता है. पिछले विधानसभा चुनाव में औपचारिक गठबंधन भले न हो सका हो, लेकिन ममता बनर्जी के आग्रह पर हेमंत सोरेन ने तुणमूल उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया था. यह संकेत था कि राजनीतिक दबावों पूरी तरह नहीं हैं. हालांकि, पिछली बार तालमेल न बन पाना झामुमो के लिए एक अधूरा अवसर साबित हुआ. संगठनात्मक सीमाएँ, सीटों के बंटवारे पर सहमति न बनना ये

नबीन पर नवीन चुनौतियां

सभी कारण तब आड़े आए. इस बार यदि झामुमो सिर्फ समर्थन तक सीमित रहता है और उसे ठोस सीटें नहीं मिलती तो उसके लिए यह फिर एक प्रतीकात्मक भूमिका बनकर रह सकती है. हालिया बिहार चुनाव में झामुमो का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. शुरुआती दौर में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को ओर से सीटें दिए जाने का संकेत मिला, लेकिन अंतिम समय में झामुमो को चुनाव लड़ने का अवसर ही नहीं मिला. भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की भूमिका पश्चिम बंगाल की सियासत में किस तरह की होगी? क्या वे सिर्फ एक बिहारी होने का वास्तव देखकर पश्चिम बंगाल में रह रहे बिहारियों से सिर्फ भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे?

बांग्लादेश में भारत के लिए विकल्प बन सकते हैं तारिक रहमान



तारिक रहमान

बांग्लादेश में राजनीतिक विभाजन गहरा है, कट्टरवादियों ने वैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, अल्पसंख्यक बुरी तरह डरे हुए हैं. शेख हसीना के कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग से जो इन संस्थाओं की छवि खराब हुई है उससे प्रशासनिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं. छात्रों के गुस्से को शांत करने वाली कोई प्रभावी आवाज देश में सुनाई नहीं पड़ती. इन सबके बीच बांग्लादेश में जनता एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में रही है, जो

स्थिरता, संतुलन और लोकतांत्रिक विश्वास बहाल कर सके. अब तारिक रहमान की वापसी को उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है.

बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव हैं. अन्वामी लीग को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और ऐसे में आम जनता के पास ज्यादा विकल्प नजर आ नहीं रहे थे. देश की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया अस्पताल में है. वहीं मैदान में जो जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी हैं, उन पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता. इसका मुख्य कारण इन दलों का राजनीतिक इतिहास, विचारधारा और व्यवहार से जुड़ी वजहें हैं. जमात-ए-इस्लामी का अतीत बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध करने, युद्ध अपराधों से जुड़े आरोपों और कट्टर इस्लामी राजनीति से जुड़ा रहा है. इसके कारण बड़ी आबादी उसे लोकतांत्रिक, समावेशी और आधुनिक राष्ट्रवाद के विपरीत मानती है. हिंसा और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने की इस दल की नीति से जनता आशंकित रही है. समावेशी राज्य व्यवस्था, अल्पसंख्यकों और उदार समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण को लेकर भी संदेह बना रहता है. शेख हसीना के विरोध के चलते है नेशनल सिटिजन पार्टी का जन्म हुआ है, लेकिन जनता इस पर दांव लगाएँ इसकी सम्भावना बेहद कम है. जनता इसके नेताओं को अवसरवादी, राजनीतिक रूप से अनिश्चित और स्थिर वैचारिक आधार से दूर मानती है. लोकतांत्रिक देशों में यह देखा गया है की कई नई पार्टियाँ अचानक उभरती हैं, सत्ता समीकरण के अनुसार झुकती-झुकाती हैं और स्थायी नीति-दृष्टि नहीं दे पाती. जनता को ऐसे दलों में नेतृत्व की स्पष्टता दिखती है, न संगठनात्मक गहराई और न ही दीर्घकालिक भरोसे का आधार. लोकतंत्र में जनता विश्वास डल दलों पर करती है जो स्थिर राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता, स्पष्ट दृष्टि और सामाजिक समावेश का भरोसा दे सकें. जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी इस कसौटी पर लोगों की नजर में कमजोर हैं, इसलिए इन दलों को सत्ता के



चुनाव के समय माहौल बना पाता है, बल्कि निरंतर संपर्क, प्रचार और जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ कर बूथ बूथ हासिल करता लेता है. बांग्लादेश की राजनीति में भी बीएनपी को उसके मजबूत केंद्र बेस के कारण गंभीर दावेदार के रूप में देखा जा सकता है. बीएनपी ने अपने शुरुआती दौर से ही छात्र, युवा, व्यापारी और स्थानीय इकाइयों के माध्यम से व्यापक नेटवर्क तैयार किया था. सत्ता से बाहर रहने और राजनीतिक दबावों के बावजूद इसका केंद्र काफी हद तक सक्रिय रहा, जो इसकी राजनीतिक उपस्थिति को जीवित रखे हुए है. तारिक रहमान की वापसी, राजनीतिक माहौल में बदलाव और सत्ता विरोधी भावना ने इस केंद्र को और ऊर्जावान बनाया है. इससे पार्टी के अंदर संगठनात्मक पुनर्गठन और जनसमर्थन जुटाने की संभावना बढ़ी है. मजबूत केंद्र के साथ रणनीतिक स्पष्टता, नेतृत्व की एकजुटता, लोकतांत्रिक विश्वसनीयता और स्थिर गठबंधन भी उतने ही आवश्यक हैं. बीएनपी अपने केंद्र को सुव्यवस्थित दिशा, स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम और जनविश्वास के साथ जोड़ पाती है, तो निश्चित ही सत्ता की संभावनाएं उसके लिए और मजबूत हो सकती हैं. तारिक रहमान ने अपने पहले ही भाषण में इसके संकेत भी दे दिए हैं. रहमान ने लोकतंत्र, कानून-व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समावेशी राजनीति की बात कर जनता में यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि एक नया बांग्लादेश बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं और इसकी वह योजना भी बना कर लाए हैं. उनकी वापसी ने देश की राजनीति में एक नया संतुलन, बहस और संभावनाओं का द्वार खोला है. यदि वे संवाद, लोकतंत्र, शांति और समावेशी शासन का रास्ता अपनाते हैं, तो सचमुच हिंसा से झुलसे बांग्लादेश के लिए वे उम्मीद साबित हो सकते हैं. हालांकि बीएनपी को सभी तबकों का विश्वास हासिल करने के लिए अभी और प्रयास करना

शीर्ष तक पहुंचने की सम्भावना बहुत कम है.

बांग्लादेश में राजनीतिक असमंजस और अविश्वास के बीच तारिक रहमान की वतन वापसी से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का दावा मजबूत हो गया है. राजनीति में मजबूत संगठनात्मक ढांचा और सक्रिय केंद्र किसी भी दल की सबसे बड़ी ताकत होते हैं. जिस दल का केंद्र जमीनी स्तर पर मजबूत होता है, वह न केवल चुनौत के समय माहौल बना पाता है, बल्कि निरंतर संपर्क, प्रचार और जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ कर बूथ बूथ हासिल करता लेता है. बांग्लादेश की राजनीति में भी बीएनपी को उसके मजबूत केंद्र बेस के कारण गंभीर दावेदार के रूप में देखा जा सकता है. बीएनपी ने अपने शुरुआती दौर से ही छात्र, युवा, व्यापारी और स्थानीय इकाइयों के माध्यम से व्यापक नेटवर्क तैयार किया था. सत्ता से बाहर रहने और राजनीतिक दबावों के बावजूद इसका केंद्र काफी हद तक सक्रिय रहा, जो इसकी राजनीतिक उपस्थिति को जीवित रखे हुए है. तारिक रहमान की वापसी, राजनीतिक माहौल में बदलाव और सत्ता विरोधी भावना ने इस केंद्र को और ऊर्जावान बनाया है. इससे पार्टी के अंदर संगठनात्मक पुनर्गठन और जनसमर्थन जुटाने की संभावना बढ़ी है. मजबूत केंद्र के साथ रणनीतिक स्पष्टता, नेतृत्व की एकजुटता, लोकतांत्रिक विश्वसनीयता और स्थिर गठबंधन भी उतने ही आवश्यक हैं. बीएनपी अपने केंद्र को सुव्यवस्थित दिशा, स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम और जनविश्वास के साथ जोड़ पाती है, तो निश्चित ही सत्ता की संभावनाएं उसके लिए और मजबूत हो सकती हैं. तारिक रहमान ने अपने पहले ही भाषण में इसके संकेत भी दे दिए हैं. रहमान ने लोकतंत्र, कानून-व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समावेशी राजनीति की बात कर जनता में यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि एक नया बांग्लादेश बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं और इसकी वह योजना भी बना कर लाए हैं. उनकी वापसी ने देश की राजनीति में एक नया संतुलन, बहस और संभावनाओं का द्वार खोला है. यदि वे संवाद, लोकतंत्र, शांति और समावेशी शासन का रास्ता अपनाते हैं, तो सचमुच हिंसा से झुलसे बांग्लादेश के लिए वे उम्मीद साबित हो सकते हैं. हालांकि बीएनपी को सभी तबकों का विश्वास हासिल करने के लिए अभी और प्रयास करना

बांग्लादेश में राजनीतिक विभाजन गहरा है, कट्टरवादियों ने वैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, अल्पसंख्यक बुरी तरह डरे हुए हैं. शेख हसीना के कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग से जो इन संस्थाओं की छवि खराब हुई है उससे प्रशासनिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं. छात्रों के गुस्से को शांत करने वाली कोई प्रभावी आवाज देश में सुनाई नहीं पड़ती. इन सबके बीच बांग्लादेश में जनता एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में रही है, जो स्थिरता, संतुलन और लोकतांत्रिक विश्वास बहाल कर सके. अब तारिक रहमान की वापसी को उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है.

बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव हैं. अन्वामी लीग को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और ऐसे में आम जनता के पास ज्यादा विकल्प नजर आ नहीं रहे थे. देश की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया अस्पताल में है. वहीं मैदान में जो जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी हैं, उन पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता. इसका मुख्य कारण इन दलों का राजनीतिक इतिहास, विचारधारा और व्यवहार से जुड़ी वजहें हैं. जमात-ए-इस्लामी का अतीत बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध करने, युद्ध अपराधों से जुड़े आरोपों और कट्टर इस्लामी राजनीति से जुड़ा रहा है. इसके कारण बड़ी आबादी उसे लोकतांत्रिक, समावेशी और आधुनिक राष्ट्रवाद के विपरीत मानती है. हिंसा और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने की इस दल की नीति से जनता आशंकित रही है. समावेशी राज्य व्यवस्था, अल्पसंख्यकों और उदार समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण को लेकर भी संदेह बना रहता है. शेख हसीना के विरोध के चलते है नेशनल सिटिजन पार्टी का जन्म हुआ है, लेकिन जनता इस पर दांव लगाएँ इसकी सम्भावना बेहद कम है. जनता इसके नेताओं को अवसरवादी, राजनीतिक रूप से अनिश्चित और स्थिर वैचारिक आधार से दूर मानती है. लोकतांत्रिक देशों में यह देखा गया है की कई नई पार्टियाँ अचानक उभरती हैं, सत्ता समीकरण के अनुसार झुकती-झुकाती हैं और स्थायी नीति-दृष्टि नहीं दे पाती. जनता को ऐसे दलों में नेतृत्व की स्पष्टता दिखती है, न संगठनात्मक गहराई और न ही दीर्घकालिक भरोसे का आधार. लोकतंत्र में जनता विश्वास डल दलों पर करती है जो स्थिर राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता, स्पष्ट दृष्टि और सामाजिक समावेश का भरोसा दे सकें. जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी इस कसौटी पर लोगों की नजर में कमजोर हैं, इसलिए इन दलों को सत्ता के

पहुंछें. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना 1978 में तारिक रहमान के पिता जनरल ज़ियाउर रहमान ने की थी. इसका मूल विचार राष्ट्रवाद, इस्लामी सांस्कृतिक पहचान और संप्रभुता को मजबूत करना रहा. बीएनपी ने खुद को राष्ट्रीय गौरव, परंपरा और मध्यमार्गी दक्षिणपंथी राजनीति के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया. 1991 में लोकतंत्र की बहाली के बाद बीएनपी ने खालिदा ज़िया के नेतृत्व में सत्ता संभाली और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा दी. शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास के कुछ कार्य उल्लेखनीय रहे, परंतु पार्टी पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक हिंसा के आरोप भी लगे. बीएनपी की छवि को लेकर जनता में असमंजस भी रहा है. एक ओर जनता के बीच राष्ट्रीयता और लोकतांत्रिक संतुलन का विकल्प, वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी ताकतों से समझौते, चुनावी बहिष्कार और आंतरिक नेतृत्व संकट की आलोचना. पिछले डेढ़ दशकों से यह पार्टी सत्ता से दूर है, ऐसे में यह लंबे संघर्ष, प्रतिबंधों, नेतृत्व के निर्वासन और विभाजन के दौर से गुजर रही है, जिससे इसकी संगठनात्मक शक्ति प्रभावित हुई है.